12 मई, 2017

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड

विशेष रिपोर्ट

ओबीओआर: बाजार, ऊर्जा और भू-राजनीतिक प्रभाव के लिए चीन की सामरिक खोज: बेल्ट एंड रोड फोरमकी पूर्व संध्या पर एक स्थिति नोट, बीजिंग, 14-15 मई 2017

*डॉ. संजीव कुमार**

चीन 14-15 मई 2017 को बीजिंग के उपनगरीय इलाके में आयोजित होने वाले " अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए बेल्ट एंड रोड फोरम" के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग मंच पर 29 देशों के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार की मेजबानी करने वाले हैं। [1]चीनी सरकार एक परिणा मी दस्तावेज के बारे में प्रतिभागियों के साथ चर्चा और परामर्श कर रही है। राज्य पार्षद यांग जिएची (प्रारंभिक कार्य के प्रभारी) ने मंच पर निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने की अपील की है: (क) पहल की प्रगति की पूरी तरह से समीक्षा कर ना, महत्वपूर्ण प्रारंभिक परिणामों का प्रदर्शन , सहयोग के लिए आगे सहमति बनाना और सहयोग की गति को बनाए रखना ; (ख) आगे किए जाने वाले प्रमुख सहयोग उपायों पर चर्चा करना,विकास रणनीतियों में अधिक तालमेल की सुविधा , साझेदारी को गहन करना और परस्पर विकास के लिए काम करना; (ग) चीन के आर्थिक-सामाजिक विकास और संरचनात्मक समायोजन को बढ़ावा देते हुए, जीत के परिणामों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए काम कर ना।[2]इसने चीन सरकार द्वारा इस तरह की पहल करने के औचित्य को समझने और पिछले तीन वर्षों में प्रदर्शन की जांच करने के लिए मंच तैयार किया है।

I

ओबीओआर: उत्पत्ति और प्रेरणाएँ

वन बेल्ट वन रोड (OBOR) मूल रूप से एशिया , अफ्रीका और यूरोप के 64 देशों में आर्थिक , ऊर्जा और कनेक्टिविटी से संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से एक प्रमुख वैश्विक स्थिति प्राप्त करने की दिशा में चीन की एक रणनीतिक परियोजना है।

एक चीनी रणनीतिकार और स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज , पेकिंग विश्वविद्यालय के पूर्व डीनप्रो. वांग जिशीने 2012 के उत्तरार्ध में " पश्चिम की ओर देखो " और " पश्चिम की ओर बढ़ो " के रणनीतिक विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने तर्क दिया कि एशिया में अमेरि का की पुनर्संतुलन रणनीति "एशिया में वापसी" पर केंद्रित हैऔर अमेरिकी रणनीति "पूर्व की ओर" बढ़ ना है। भारत, रूस और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक खिलाड़ियों ने अपनी भू-रणनीतियों को समायोजित किया था और अब वे पूर्व की ओर देखने लगे हैं। इस संदर्भ में, चीन को "पश्चिम की ओर बढ़ो" की रणनीतिक योजनाएं बनानी चाहिए। वांग ने तर्क दिया कि चीन को दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और कैस्पियन सागर क्षेत्र के सभी देशों के साथ आर्थिक और व्यापार सहयोग बढ़ाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि इन क्षेत्रों में यूरोपीय संघ, रूस, भारत, अमेरिका, जापान और चीन के महत्वपूर्ण हित मिलते और प्रतिस्पर्धा करते हैं। पश्चिमी यूरोप और पूर्वी एशिया के विपरीत , दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और कैस्पियन सागर क्षेत्र के देशों में "न तो अमेरिका के नेतृत्व में क्षेत्रीय सैन्य गठबंधन (या विरोधी गठबंधन) है, और न ही हो सकता है।[3]

उल्लेखनीय है कि पूर्वी एशिया में चीन के नेतृत्व की महत्वाकांक्षाओं को चुनौती दी गई है। इसलिए, चीनी नेतृत्व की पांचवीं पीढ़ी को पूर्वी एशिया में चीन के पारंपरिक कारावास से दूर होने के लिए प्रेरित किया गया था।[4]"पश्चिम की ओर बढ़ो" को चीन के शीर्ष नेतृत्व द्वारा गंभीरता से लिए जाने का यह मुख्य कारण हो सकता है। दूसरे, यह चीन को अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए एक वैकल्पिक भौगोलिक क्षेत्र प्रदान करेगा। इसके अलावा , "मार्च वेस्ट" पूर्वी और तटीय प्रांतों की तुलना में चीन के पश्चिमी प्रांतों में हुए कम विकास के आलोक में विकास को बढ़ावा देने के लिए 2000 में शुरू की गई राष्ट्रीय रणनीति "पश्चिमी विकास रणनीति" को गति देगा।

ओबीओआर पहल का क्रमिक विकास निश्चित रूप से वांग द्वारा सुझाए गए से अधिक व्यापक है। हालांकि, यह कहा जा सकता है कि "मार्च वेस्ट" के लिए वांग जिशी के तर्क ने चीन की ओबीओआर पहल के लिए रणनीतिक औचित्य प्रदान किया।

जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सितंबर 2013 में मध्य एशिया और अक्टूबर 2013 में दक्षिण पूर्व एशिया का दौरा किया, तो उन्होंने पहली बार सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और 21वीं सदी की समुद्री सिल्क रोड के निर्माण की पहल के बारे में बात की। मार्च 2015 में , राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग, विदेश मंत्रालयऔर पीआरसी के वाणिज्य मंत्रालय ने राज्य परिषद के प्राधिकरण के साथ"संयुक्त सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और 21वीं सदी के समुद्री सिल्क रोड के निर्माण पर दृष्टि और क्रियाएं"दस्तावेजको जारी किया (विजन डॉक्यूमेंट)। बाद में , इस पहल को "वन बेल्ट एंड वन रोड (OBOR)" का नाम दिया गया । अंततः इसका नाम बदलकर बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) कर दिया गया। हालाँकि, पहल को अभी भी चीनी भाषा में यी दाई यी लु (一带一路)के नाम से ही जाना जाता है। यह पत्र ओबीओआरशब्द का उपयोग करेगा।

दृष्टि दस्तावेज में लिखा है कि सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट चीन , मध्य एशिया, रूस और यूरोप (बाल्टिक) को एक साथ लाने पर केंद्रित है ; मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के माध्यम से चीन को फारस की खाड़ी और भूमध्य सागर से जोड़ ता है; और चीन को दक्षिण -पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया और हिंद महासागर से जोड़ता है। 21वीं सदी की मैरीटाइम सिल्क रोड को दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर के माध्यम से चीन के तट से सीधे मार्ग द्वारा यूरोप जाने तथा चीन के तट से दक्षिण चीन सागर के माध्यम से दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है [5] (देखेंनक्शा 1)।तालिका मार्ग और क्षेत्र के साथ देशों के नाम प्रदान करती है। 15 अप्रैल 2015 को चाइना डेली में एक नया नक्शा प्रकाशित किया गया था जहाँ चीनी सरकार ने दक्षिण एशिया और दक्षिण प्रशांत को आधिकारिक मार्ग में शामिल किया था (मानचित्र 2 देखें)। प्रारंभिक नक्शे में ओबीओआर के भूमि मार्ग में दक्षिण एशिया शामिल नहीं था , हालांकि, अप्रैल 2015 में चीन द्वारा जारी संशोधित मानचित्र में दक्षिण एशिया शामिल है।

मानचित्र 1: OBOR के मार्ग

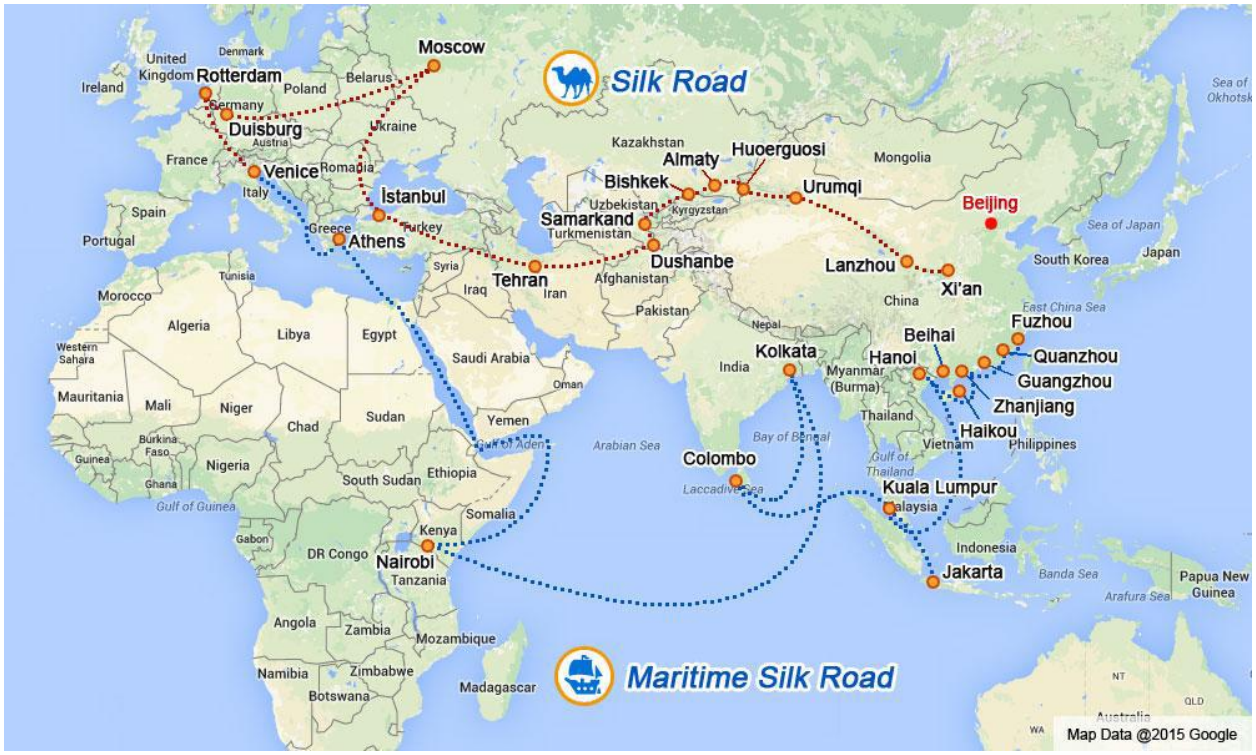

स्रोत: सिन्हुआ वित्त एजेंसी

तालिका: चीन प्लस 64 देश

पूर्वी एशिया	चीन, मंगोलिया
दक्षिण-पूर्वी एशिया	ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर-लेस्टे, वियतनाम
मध्य एशिया	कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान
पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका	बहरीन, मिस्र, ईरान, इराक, इजरायल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, फिलिस्तीन, सीरिया, संयुक्त अरब अमीरात, यमन
दक्षिण एशिया	अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका
यूरोप	अल्बानिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, जॉर्जिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, मैसेडोनिया, मोल्दोवा, मोंटेनेग्रो, पोलैंड, रोमानिया, रूस, सर्बिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, तर्की, यूक्रेन

मानचित्र 2: ओबीओआर का संशोधित मार्ग

श्रोत: चाइना डेली

रणनीतिक लाभ के अलावा, ओबीओआर की शुरुआत के लिए आर्थिक लाभ एक प्रमुख कारक रहा है। इसने 65 देशों को शामिल करने वाली एक परियोजना पर चीन सरकार केमहती प्रयास का संकेत दिया, आंशिक रूप से घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूरी के कारण जो कि पुनर्गठन और संसाधन प्रबंधन पर केंद्रित थी। इस संदर्भ में, चीन की आर्थिक स्थिति का संक्षिप्त विश्लेषण करना यहाँ तर्कसंगत है।

चीन की आर्थिक वृद्धि 21वीं सदी का एक महत्वपूर्ण विकास है। चीन ने तीन से अधिक दशकों में दोहरे अंकों में वृद्धि पाई है, यह विश्व अर्थव्यवस्था का 'विनिर्माण केंद्र' बन गया और दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक इकाई के तौर पर जापान को पछाड़ दिया। उच्च विकास दर (1978-2011) की अवधि खत्म हो गई है और ची नी सरकार ने खुद को एक 'नए सामान्य' के लिए प्रतिबद्ध किया है। वर्तमान में अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तनों से गुजर रही है और 2014 में इसने 7.3 प्रतिशत, 2015 में 6.9 प्रतिशत और 2016 में 6.7 प्रतिशत की अपेक्षाकृत धीमी प्रगति देखी।

विकास के चीनी मॉडल ने चीन में संपत्ति का सृजन किया; हालाँकि, इसके परिणामस्वरूप गंभीर विकासात्मक और सामाजिक समस्याएं पैदा हुईं। सुधार के युग में चीन के पूर्वी या तटीय क्षेत्रों में

केन्द्रित वृद्धि देखी गई, क्षेत्रीय भिन्नता तथा आय एवं धन में असमानता के मुद्दे ने साबित किया कि विकास का वितरण उचित नहीं है। कुछ विद्वानों ने तो इसे संकट तक बताया। यह सुझाव दिया गया है कि यदि समस्या हल नहीं हुई है, तो 'मध्य-आय जाल' एक वास्तविकता हो सकती है।[6]

इस पृष्ठभूमि में , विज़न डॉक्यूमेंट में उल्लेख किया जाना तर्कसंगत है कि "बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने में , चीन अपने विभिन्न क्षेत्रों के तुलनात्मक लाभ का पूरी तरह से फायदा उठाएगा, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों के बीच संपर्क और सहयोग को मजबूत करने , सम्बन्धों को आगे बढाने के लिए एक सक्रिय रणनीति अपनाएगा ,और व्यापक रूप से चीनी अर्थव्यवस्था के खुलेपन में सुधार करेगा।"यह चीन के अपने घरेलू दृष्टिकोण से ओबीओआर के महत्व पर प्रकाश डालता है।

यांग जिएची ने हाल ही में (फरवरी 2017) पुष्टि की है कि ओबीओआर "चीन की क्षेत्रीय विकास रणनीति, नई शहरीकरण रणनीति और खुलेपन की रणनीति का निकटता से पालन करता है और यह चीन के सभी आया मों को शुरू करने को मजबूती से बढ़ावा देगा।" इसलिए, चीन की घरेलू अर्थव्यवस्था को लाभ ओबीओआर के लिए एक प्रमुख चालक बना हुआ है। इसके अलावा , ओबीओआरचीन के आर्थिक पुनर्गठन, औद्योगिक उन्नयन के साथ-साथ "वैश्विक रूप से आगे बढ़ने" की रणनीति के लिए अवसर प्रदान करता है।

आर्थिक मंदी के युग मेंचीन में , नए बाजार बना कर और बुनियादी ढांचे (सड़क , रेलवे आदि) और औद्योगिक गलियारों का निर्माण करके तथा बंदरगाहों/केन्द्रों के साथ औद्योगिक परिसरों की स्थापना और क्षेत्र में परिवहन एवं संचार नेटवर्क का निर्माण करके आर्थिक लाभ प्राप्त करने की योजना है।यह कोई दानार्थ परियोजना नहीं है और चीनी कंपनियों के लिए नया बाजार बनाने के बारे में है।

ऊर्जा

चीनी अकादमी ऑफ सोशल साइंसेज (सीएएसएस) के इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटिक एंड टेक्निकल इकोनॉमिक्स (आईक्यूटीई) द्वारा 2015 के एक अध्ययन में कहा गया है, "चीन एक अत्यंत गंभीर ऊर्जा सुरक्षा स्थिति का सामना कर रहा है।"[7]जून 2014 को वित्तीय और आर्थिक मामलों की सेंट्रल लीडिंग ग्रुप की छठी बैठक में बोलते हुए , शी जिनपिंग ने जोर दिया कि चीन ओबीओआर के माध्यम से ऊर्जा सहयोग को प्रोत्साहित करेगा और परियोजना के क्रियान्वन के दौरान मध्य एशिया , पश्चिम एशिया, अमेरिका और अफ्रीका के देशों के साथ तेल और गैस सहयोग का विस्तार करेगा। उन्होंने कहा , "हम ऊर्जा अन्वेषण और निष्कर्षण में अपने प्रयासों को भी तेज करेंगे, ... ऊर्जा क्षेत्र में कानूनों और नियमों को बनाने, संशोधित करने और निरस्त करने के लिए पहल शुरू करेंगे।"[8]

गौरतलब है कि आईक्यूटीई ने अपने अध्ययन में कहा है कि ओबीओआरको एक न या क्षेत्रीय ऊर्जा बाजार बनाने के लिए मध्य एशिया , पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया और दक्षिण एशिया के ऊर्जा संसाधनों और उपभोग बाजार को जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करने के लिहाज से बनाया गया है। यह एक एकल पाइपलाइन के माध्यम से एक निश्चित आपूर्ति संबंध बनाने के बजाय क्षेत्र के समृद्ध ऊर्जा संसाधनों का प्रभावी ढंग से फायदा उठाएगा। [9] आईक्यूटीईअध्ययन के आधार पर, चीन की ओबीओआरपहल के ऊर्जा घटक का विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर विश्लेषण करना तर्कसंगत है।

पूर्वोत्तर एशिया: चीन की ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से रूस और मंगोलिया महत्वपूर्ण देश हैं। ओबीओआर के कार्यान्वयन ने रूस और मंगोलिया से चीन को ऊर्जा आपूर्ति की अधिक संभावनाएं प्रदान की हैं। ओबीओआर पर आईक्यूटीई के अध्ययन से पता चलता है कि "अगर पावर ग्रिड इंटर कनेक्शन और तेल एवं गैस बाजार एकीकरण रूसी सुदूर पूर्व, पूर्वोत्तर चीन, चीन के बोहाई सागर और उत्तर कोरिया से प्राप्त किया जाता है, तो भविष्य में एक नया विकास ध्रुवदिखने की संभावना है।"[10]

दक्षिण-पूर्व एशिया: कुल मिलाकर , दक्षिण-पूर्व एशिया तेल और गैस संसाधनों में समृद्ध है। अध्ययन में कहा गया है कि दक्षिणी चीन के पास एक अच्छा औद्योगिक आधार है , लेकिन ऊर्जा संसाधन कम हैं। दक्षिण-पश्चिम चीन, मेकांग नदी घाटी और म्यांमार में प्रचुर जल संसाधन हैं , लेकिन औद्योगिक आधार कमजोर है। मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई के पास प्रचुर मात्रा में तेलसंसाधन हैं , लेकिन उनके पास इसके मुताबिक औद्योगिक प्रणाली नहीं हैं।[11]

ऐसा लगता है कि चीन के विभिन्न क्षेत्र खुद को ऊर्जा संसाधनों के गंतव्य के रूप में पेश करेंगे और पड़ोसी देशों को चीन को औद्योगिक शक्ति के रूप में विकसित करने में मदद के लिए ऊर्जा संसाधनों के आपूर्तिकर्ता के रूप में।

अध्ययन पश्चिम चीन, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में ऊर्जा बाजारों को जोड़ने के बारे में भी बताता है। यह भविष्य में ईरान, अफगानिस्तान, चीन, भारत और पाकिस्तान के साथ एक ऊर्जा नेटवर्क का भी सुझाव देता है। अध्ययन में सिफारिश की गई है कि चीन के 'तेल के लिए बुनियादी ढांचे' के सिद्धांतको और अधिक विस्तारित तथा क्रियान्वित किया जाना चाहिए क्योंकि इससे ओबीओआर के बीच बुनियादी ढाँचे के विकास में और तेजी आएगी।[12]फिर से,चीन के लिए 'तेल के लिए बुनियादी ढाँचा ' का मॉडल अफ्रीका में सफल रहा था। यह अन्य देशों के लिए उपयुक्त नहीं भी हो सकता है।

भू-राजनीतिक प्रभाव

अब, यह अच्छी तरह से प्रलेखित है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में निम्न प्रोफ़ाइल रखने के लिए डेंग जियाओपिंग के "24 चरित्र दिशानिर्देशों" को शी जिनपिंग द्वारा दरकिनार कर दिया गया है। चीन का दीर्घकालिक लक्ष्य एशिया के साथ-साथ विश्व में एक प्रमुख शक्ति बनना है। चाइना ड्रीम या चीनी राष्ट्र के महान कायाकल्प की अवधारणा को आगे बढ़ाने का श्रेय राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दिया जाता है।

राष्ट्रपति शी ने चीनी सपने को एक मजबूत राज्य , राष्ट्र का कायाकल्प और लोगों के खुशहाल जीवन के रूप में उजागर किया है। [13]पार्टी कांग्रेस के बाद , राष्ट्रपति शी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि चीन दो महान लक्ष्यों की ओर बढेगा। पहला लक्ष्य 2021 तक "हर तरह से एक समृद्ध समाज का निर्माण" करना है। दूसरा, 2049 तक "आधुनिक समाजवादी देश" बन ना, यानि कि "समृद्ध, मजबूत, लोकतांत्रिक, सांस्कृतिक रूप से उन्नत और सामंजस्यपूर्ण"। [14]चीनी नेतृत्व ने बताया कि "चीनी सपने की महत्वपूर्ण सोच ने चीनी राष्ट्र के महान नवीकरण को पूरा करने में न केवल हमारे लोगों के दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास को बढाया है, बल्कि दुनिया में चीन की अपील और प्रभाव को काफी बढ़ाया है , अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हमारे कद और आवाज को ऊंचा किया है और हमारे घरेलू और बाहरी एजेंडे के बीच मजबूत तालमेल को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त किया है।"[15]

चीनी विशेषज्ञों ने स्वीकार किया है कि "सीपीसी की 18वीं राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद से चीनी विदेश नीति की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक राष्ट्रीय हित को अधिक महत्व देने से जुड़ा है।"[16] प्रोफेसर वांग जिशी ने जोर देकर कहा है कि अपनी समग्र राष्ट्रीय भू-रणनीति विकसित करने के दौरान चीन खुद को उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के मध्य में मान सकता है। [17] यह "मध्य राज्य सिंड्रोम" के साथ प्रतिध्वनित होता है जो अनसुलझे क्षेत्रीय/समुद्री विवादों पर नीति के परिवर्तन में काफी हद तक स्पष्ट है। क्यू शी में यांग जिएची का आलेख (सत्य की तलाश) दक्षिण चीन सागर विवाद के संदर्भ में "शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में क्षेत्रीय संप्रभुता" पर जोर देता है।[18]

राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने " साझा नियति का समुदाय" बनाने की भी बात की है। हालाँकि, "चीन की 'साझा नियति'का दृष्टिकोण समस्याजनक हो सकता है क्योंकि यह मानता है कि एशिया के सभी देश वही चाहते हैं जो चीन चाहता है। चीन के अनुसार , 'साझा नियति' के वैश्विक भू-राजनीति और मौजूदा एशियाई राजनीतिक व्यवस्था के लिए बड़े निहितार्थ हैं ... 'एशिया के लिए एशिया' की चीनी नेतृत्व वाली अवधारणा को बढ़ावा देकर, बीजिंग अपने प्रस्तावों और एशियाई देश स्वयं जो भी करना चाहते हैं, उनके बीच प्रतिस्पर्धा पैदा कर रहा है।"[19]

II

इसमें शामिल चुनौतियां और जोखिम

ओबीओआर योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी टीम के लिए शायद सबसे बड़ी चुनौती होगी क्योंकि इसमें कई गंभीर जोखिम शामिल हैं।

पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स (PIIE) का एक अध्ययन बताता है कि चीन की ओबीओआरपहल तीन स्व-प्रेरित चुनौतियों का सामना कर रही है। सबसे पहले है परियोजनाओं का कार्यान्वयन। चीनी कंपनियों की कुछ उल्लेखनीय विफलताएँ हैं , जैसे कि चीनी ओवरसीज इंजीनियरिंग समूह द्वारा पोलैंड के ए2 राजमार्ग का निर्माण और तुर्की में ची नी मशीनरी इंजीनियरिंग निगम द्वारा

सौदे को रद्द किया जाना। दूसरी चुनौती वित्त के लिए परियोजनाओं का चयन है। चीनी बैंक अलाभकारी उपक्रमों में निवेश के अधिक जोखिम में हो सकते हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती अर्थशास्त्र और राजनीति को अलग-अलग रखना है और मुख्य रूप से राजनीतिक कारणों से परियोजनाओं का समर्थन नहीं करना है।[20]

रेनमिन विश्वविद्यालय, बीजिंग के स्कूल ऑफ़ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वांग यीवेई ने अपने पुरस्कार प्राप्त अध्ययन में ओबीओआर पहल के जोखिमों को रेखांकित किया है। [21]पहली समस्या राजनीतिक जोखिम है , जिसे दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: विभिन्न देशों के घरेलू राजनीतिक जोखिम और भू-राजनीतिक जोखिम। दूसरी समस्या सुरक्षा जोखिम है, जिसे पारंपरिक और गैर पारम्परिक सुरक्षा में विभाजित किया जा सकता है। इसमें शामिल हैं: (ए) प्राकृतिक जोखिम (बी) पर्यावरण जोखिम (सी) चरमपंथी ताकतों का खतरा (डी) गैर-सरकारी संगठनों का खतरा (ई) समुद्री सुरक्षा जोखिमों का खतरा। निम्नलिखित पहलुओं में आर्थिक जोखिमों को दिखाया गया है: (ए) मैक्रो जोखिम जैसे कि एआईआईबी और सिल्क रोड फंड की संभावित समस्याएं (बी) औद्योगिक जोखिम-न केवल चीन और उसके उद्योग के 'वैश्विक' होने की अति-क्षमता के बारे में समस्याएं , बल्कि मार्ग में आने वाले देशों के लिए औद्योगिक सुधार को प्राप्त करना भी, और (सी) जोखिम प्रतिक्रिया तंत्र की कमी। कानूनी जोखिम भी महत्वपूर्ण हैं। चीन ने अपनी खुद की समाजवादी कानूनी प्रणाली को अपनाया है, जो मार्ग में आने वाले 64 देशों से अलग है। कानूनी जोखिम निवेश , श्रम, पर्यावरण संबंधी चिंताओं , खराब प्रबंधन आदि से संबंधित मुद्दों के कारण हो सकते हैं।इसके अलावा , यह मार्ग में आने वाले देशों के विभिन्न कानूनों के कारण हो सकता है। अंत में , उद्यम के स्तर पर, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय, ओबीओआर पहल द्वारा सामना किए जाने वाले नैतिक जोखिम भी समस्या का कारण हो सकते हैं।[22]

उपरोक्त चुनौतियों और शामिल जोखिमों के अलावा , यह तर्क देना उचित है कि ओबीओआरके कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित मुद्दे महत्वपूर्ण साबित होंगे। (ए) विवादित क्षेत्रों और प्रदेशों की बात आने पर चीन को अंतरराष्ट्रीय कानून और प्रथाओं का सम्मान करना होगा, अन्यथा, संतुलन और प्रतिसंतुलन सफल कार्यान्वयन की संभावनाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। (बी) चीन के निवेश के मॉडल को कई देशों ने नहीं सराहा है। आमतौर पर , चीनी कंपनियां चीनी सामग्री और उपकरणों के साथ-साथ श्रम का भी आयात करती हैं। यह स्थानीय आबादी के बीच तनाव पैदा करता है। कजाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों के स्थानीय विरोध प्रदर्शनों में यह स्पष्ट था। इसके अलावा , 2013-15 में चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ़ चाइना द्वारा लोन प्राप्ति के एक अध्ययन से पता चला कि 70 प्रतिशत विदेशी क्रेडिट इस शर्त पर हुआ था कि फंड के कम से कम एक भाग का इस्तेमाल चीनी उपकरण खरीदने के लिए किया जाए और इसमें चीनी श्रमिक शामिल रहेंगे।[23]इस प्रकार, चीन के निवेश के मॉडल को गंभीरता से सुधार की आवश्यकता है। (सी) अंत में, प्रौद्योगिकी का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। चीन अत्याधुनिक और कोर प्रौद्योगिकियों के मामले में पीछे है। आर्थिक पुनरुत्थान और उन्नयन के युग में पिछले युग की तकनीकी को पड़ोसी देशों में हस्तांतरित करना उचित नहीं होगा।

III

ओबीओआर के शुरुआती नतीजे

स्टेट काउंसलर यांग जिएची और विदेश मंत्री वांग यी एवं चीनी विशेषज्ञों ने ओबीओआर के शुरुआती नतीजों पर प्रकाश डाला है। [24] (ए) चीन ने ओबीओआर मार्ग में आने वाले देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। अब तक 34 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने ओबीओआरके निर्माण के लिए चीन के साथ अंतरसरकारी सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके आधार पर विस्तृत सहयोग योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। (बी) वित्तीय सहायता तंत्र आकार ले रहा है। एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) ने 2017 की शुरुआत से काम करना शुरू कर दिया है। सिल्क रोड फंड ने औपचारिक रूप से निवेश परियोजनाओं की अपनी पहली खेप जारी कर दी है (सी) औद्योगिक क्षमता सहयोग में विकास को गति मिली है। चीन ने व्यवस्थित औद्योगिक क्षमता सहयोग शुरू करने के लिए 20 से अधिक देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। विभिन्न देशों में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं (डी) कनेक्टिविटी: वर्तमान में, हंगरी और सर्बिया के बीच रेलवे का निर्माण, और इंडोनेशिया में हाई-स्पीड रेलवे शुरू हो गया है। चीन और लाओस तथा चीन और थाईलैंड को जोड़ने वाले रेलवे नेटवर्क का निर्माण शुरू हो गया है। कई हाईवे परियोजनाओं के निर्माण का काम भी शुरू हो गया है। (एफ) आर्थिक गलियारे के निर्माण की ओर महत्वपूर्ण विकास हुआ है। (जी) व्यापार और निवेश: 2015 में, चीनी उद्यमों ने ओबीओआर से संबंधित 49 देशों में प्रत्यक्ष निवेश किया, जिसकी कुल राशि 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी।

हालाँकि, यह एक तथ्य है कि चीन द्वारा शुरू की गई बुनियादी ढाँचे की कई परियोजनाएँ ओबीओआर पहल से जुड़ी हैं। उदाहरण के लिए , मध्य एशिया में गैस पाइपलाइन तथा रेल और सड़क निर्माण परियोजनाएं चीन ने ओबीओआर की घोषणा से पहले बनाई थीं, लेकिन अब यह उनके इसी पहल का हिस्सा होने का दावा करता है।

इसके अलावा, एआईआईबी की स्थापना को ओबीओआर परियोजनाओं के वित्तपोषण के उद्देश्य से बनाए गए बैंक के रूप में बताया गया है। इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि जब इसे स्थापित किया गया था तो यह बैंक का एकमात्र उद्देश्य नहीं था।

यह ध्यान रखना उचित है कि सरकार ने चीन के क्षेत्रीय और प्रांतीय विकास पर ओबीओआर के कार्यान्वयन के प्रभाव को चिह्नित नहीं किया है (जैसा कि दृष्टि दस्तावेज और अन्य आधिकारिक बयानों में प्रकाश डाला गया है)। चीन ने 20 अक्टूबर 2016 को बीजिंग में अपनी पहली बड़ी डेटा रिपोर्ट "बेल्ट एंड रोड इन बिग डेटा" जारी की। रिपोर्ट के अनुसार , चीन में गुआंगडोंग, झेजियांग, शंघाई, तियानजिन, फुजियान, शानदोंग, हेनान, युन्नान और बीजिंग शीर्ष दस सबसे सक्रिय भागीदार हैं। यह दर्शाता है कि ओबीओआरने चीन की क्षेत्रीय विकास रणनीति पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डाला है। चीन के तटीय और पूर्वी क्षेत्र ओबीओआरके सबसे सक्रिय भागीदार हैं। इसके अलावा , बिग डेटा रिपोर्ट में कहा गया है कि

मार्ग के देशों के साथ व्यापार के परिमाण को लेकर गुआंगडोंग प्रांत सम्पूर्ण राष्ट्र में 20.9 प्रतिशत के साथ सभी चीनी प्रांतों में सबसे ऊपर है। ग्वांगडोंग के बाद जिआंगसू, झेजियांग और बीजिंग हैं। गौरतलब है कि इससे चीन में क्षेत्रीय असमानता की समस्या बढ़ सकती है।

इसके अलावा, अभी भी व्यक्तिगत या संपूर्ण परियोजना के लिए बड़ी लागत के साथ-साथ वित्तीय तंत्र को लेकर अस्पष्टता है। चीन को कई देशों के साथ 'ऋणजाल'की आशंका के मुद्दे पर स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए।

ओबीओआर पहल की सफलता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करेगी: (ए) परियोजनाओं के कार्यान्वयन में शामिलराजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा, कानूनी, नैतिक, तकनीकी जोखिमों और चुनौतियों से चीन कैसे निपटता है? जोखिम काफी गंभीर और जटिल हैं और उनमें विफलता का उच्च प्रतिशत/संभावना है; (बी) मार्ग में आने वाले देशों को क्या मिलता है, खासकर उनके आर्थिक विकास और सुरक्षा के संदर्भ में?प्रत्येक देश अवसंरचनात्मक और अन्य परियोजनाओं से लाभ का आकलन करेगा ; (सी) चीन क्षेत्रीय हितधारकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। संतुलन और मुखरता की नीति अनुत्पादक साबित हो सकती है, जैसा कि पूर्वी एशिया में हुआ। चीन को एशिया में क्षेत्रीय हितधारकों के हितों और आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है।

IV

दक्षिण एशिया में ओबीओआरकी रूपरेखा में परिवर्तन

सितंबर 2014 में आईसीडब्ल्यूए द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में अपने संबोधन में , राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा "ओबीओआर की सहायता से, चीन दक्षिण एशिया के साथ मिलकर यात्रा करना चाहता है।"[25]उन्होंने दक्षिण एशिया को सहायता के बारे में भी बात की। "संदेश यह था कि चीन दक्षिण एशिया का पड़ोसी है और भारत इस क्षेत्र में आज़ादी से नहीं बढ़ पाएगा । वास्तव में चीन इस शताब्दी की शुरुआत से ही दक्षिण एशिया के लिए एक अलग दृष्टिकोण का निर्माण कर रहा है।"[26]इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हाल के वर्षों में चीनी विद्वानों ने चीन-दक्षिण एशिया संबंधों के लिए 'न्यू स्प्रिंगटाइम' और 'दक्षिण एशिया की सामरिक स्थिति का पुन:अन्वेषण' जैसे शब्दों का उपयोग किया है।[27]

यहाँ ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि दक्षिण एशिया मूल रूप से ओबीओआर का हिस्सा नहीं था, फिर भी इसका उल्लेख विज़न डॉक्यूमेंट के खंड III में पहल के ढांचे की रूपरेखा को चिह्नित करने के लिए किया गया था। [28] इसके अलावा , विज़न डॉक्यूमेंटकहता है, "चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार आर्थिक गलियारा बेल्ट एंड रोड पहल से निकटता से संबंधित हैं। प्रारंभ में , ओबीओआर के आधिकारिक मानचित्र में सीपीईसी या बीसीईएम शामिल नहीं थे।

आज, चीन में सीपीईसी को ओबीओआर की सर्वप्रमुख परियोजना के रूप में परिभाषित करने की प्रवृत्ति हो गई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता होंग लेई ने 20 अप्रैल 2015 को बताया, "चीन-

पाकिस्तान आर्थिक गलियारा वह जगह है जहाँ सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और 21वीं सदी की मैरीटाइम सिल्क रोड मिलते हैं। *इसलिए, यह "बेल्ट एंड रोड" पहल की एक प्रमुख परियोजना है।*[29]

जब विदेश मंत्री वांग यी ने मई 2016 में ओबीओआर के शुरुआती नतीजों के बारे में बात की, तो उन्होंने कहा "चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जल्दी शुरू हुआ और तेजी से विकसित हुआ , जिसमें कई प्रमुख परियोजनाएं शुरू हुई ...चीन-बांग्लादेश-भारत-म्यांमार आर्थिक गलियारा लगातार विकसित हो रहा है।"[30]स्टेट काउंसलर यांग जिएची ने फरवरी 2017 में पीपुल्स डेली और चाइना डेली को दिए अपने साक्षात्कार में आर्थिक गलियारे के निर्माण को ओबीओआर की शुरुआती सफलता के रूप में उल्लेख किया। कई चीनी विशेषज्ञों और मीडिया के लिए , सीपीईसीअब समग्र ओबीओआरका हिस्सा है।यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि "चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भारत की संप्रभुता की मुख्य चिंताओं पर प्रभाव डालता है और अब इसे ओबीओआर के हिस्से के रूप में दिखाया जा रहा है, जिससे जाहिर तौर पर भारत भी ओबीओआर को लेकर सतर्क हो गया है।"[31]इसके अलावे, बीसीआईएम सहयोग की प्रक्रिया लगभग 15 साल पहलेशुरू हुई थी। बीसीआईएम को ओबीओआर पहल की प्रारंभिक उपलब्धि के रूप में उद्धृत करना गलत होगा।

निष्कर्ष

आधिकारिक घोषणाओं के अनुसार , 14-15 मई 2017 को बीएआर फोरम के दौरान एक स्पष्ट रोडमैप और कार्ययोजना सामने आएगी। प्रतिभागी देश प्रमुख सहकारी परियोजनाओं की पहचान कर सकते हैं और वित्तपोषण समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। नीति समन्वय और विकास रणनीतियों के बीच संबंध, कनेक्टिविटी, आर्थिक और व्यापार सहयोग , निवेश और वित्तपोषण प्रणालियों , लोगों से लोगों के संबंधों और थिंक टैंक संचार के कनेक्शन परछह समानांतर पैनल में चर्चा होने की उम्मीद है। इसके अलावा, यह उल्लेखनीय है कि उत्तर कोरिया का एक मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल फोरम में भाग लेगा। उत्तर कोरिया ओबीओआर के प्रस्तावित मार्ग पर नहीं है। उत्तर कोरिया की भागीदारी के लिए केवल रणनीतिक कारण हो सकते हैं।

अंत में, यह कहा जा सकता है कि ओबीओआरएशियाई और विश्व मामलों में बाजार, संसाधनऔर प्रभुत्व हासिल करने के लिए चीन का एक दीर्घकालिक और रणनीतिक एजेंडा है। इस पहल का टकराव प्रमुख एशियाई और गैर-एशियाई देशों के हितों और आकांक्षाओं के साथ हो सकता है। गौरतलब है कि ओबीओआरने दक्षिण एशिया के रणनीतिक महत्व को दृढ़ता दी है और चीन क्षेत्रीय हितधारकों की चिंताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। यहां तक कि चीनी विद्वान भी इस बात से सहमत हैं कि भारत की प्रगति, अफगानिस्तान से विदेशी ताकतों के हटने और चीन के पश्चिमी विकास रणनीति के एक नए चरण में प्रवेश करने जैसे कारकों ने दक्षिण एशिया को महत्वपूर्ण सामरिक महत्व का क्षेत्र बना दिया है।

***

*डॉ. संजीव कुमार, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, सप्रू हाउस, नई दिल्ली, में रिसर्च फेलो हैं।
अस्वीकरण: व्यक्त किए गए विचार शोधकर्ता के हैं, परिषद के नहीं।